साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

भोपाल, सोमवार, 22-8 नवंबर 2021, वर्ष-7, अंक-34

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

चौपाल से भोपाल तक

14 माह बाद तीनों कृषि कानून वापस, पीएम मोदी ने कानून वापसी का किया ऐलान

› भाजपा ने एक ही झटके में विपक्ष के हाथों से छीन लिया मुद्दा

› मप्र के कृषि मंत्री बोले-हम किसानों को समझाने में असफल

जय किसान

भोपाल। संवाददाता

किसानों के हठ के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इस ऐलान के लिए दिन चुना गया प्रकाश पर्व का। पीएम ने राष्ट्र के नाम 18 मिनट के संबोधन में यह बड़ा ऐलान किया। पीएम की इस घोषणा ने दुनिया भर को चौंका दिया। साथ ही विपक्ष के हाथों से एक ही झटके में मुद्दा छीन लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नीयत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। प्रधानमंत्री ने संबोधन की शुरुआत में कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों आज देव दीपावली का पावन पर्व है। मैं विश्व में सभी लोगों और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। यह भी बेहद सुखद है कि डेढ़ साल बात करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिर से खुल गया है। शुभकामनाएं देने के बाद मोदी ने किसानों के हित में अपनी सरकार के काम और योजनाएं गिनाईं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार की 10 हजार एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने की प्लानिंग है। हमने एमएसपी और क्रॉप लोन बढ़ा दिया है। यानी हमारी सरकार किसानों, खासतौर पर छोटे किसानों के हित में लगातार एक के बाद एक कदम उठाती जा रही है। इसी अभियान में तीन कृषि कानून लाए गए थे, ताकि किसानों को फायदा हो।

क्षमा, तपस्या, पवित्र, प्रकाश, सत्य

पीएम ने कहा कि साथियों, मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए, सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी जिसके कारण दीये के प्रकाश जैसा सत्य, कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाया। आज मैं आपको, पूरे देश को यह बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है।

यह समय किसी को दोष देने का नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने किसानों को समझने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था उन्हें बदलने को भी तैयार थे। साथियों आज गुरु नानक देवजी का पवित्र पर्व है। यह समय किसी को दोष देने का नहीं है। गुरु नानक देव ने कहा है कि संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है।

» 2022 : यूपी, पंजाब सहित 5 राज्यों में अगले साल होंगे चुनाव

» नया मोर्चा-कानून वापस होने के बाद ही आंदोलन होगा खत्म

» कमलनाथ ने कहा- अहंकारी सरकार को किसानों ने झुकाया

» शिवराज बोले-पीएम ने हमेशा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया

किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता

देश के हर 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इनकी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। हमने किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। हमारी सरकार ने फसल बीमा योजना को प्रभावी बनाया। 22 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। छोटे किसानों को ताकत देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

कौन से कानून होंगे वापस

» **कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020**- इससे किसानों को अपनी उपज के लिए वृहद बाजार मिलता। वह कहीं भी फसल बेच सकते।

» **कृषक (सशक्तिकरण-संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020**- इस कानून के तहत किसान निजी क्षेत्र के साथ करार कर अपनी आय बढ़ाने का उपक्रम कर सकते।

» **आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020**- इसके अंतर्गत कृषि के कई उत्पादों को जमा करने की सीमा हटा दी गई थी।

» **कैसे वापस होंगे कानून**-कानून वापसी के संशोधन के लिए कृषि मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके बाद कृषि मंत्री संसद में इस आशय का बिल पेश करेंगे। बिल पर बहस और वोटिंग होगी।

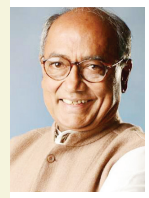

मोदी जी! देर से आए, दुरुस्त आए

पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने लिखा- मोदी जी को धन्यवाद। देर से आए दुरुस्त आए। जीत गया भाई जीत गया, किसान आंदोलन जीत गया। जनता की ताकत के आगे सरकार की तानाशाही नहीं टिकती है।

सराहनीय निर्णय

भाजपा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने पर हर्ष जताया। उन्होंने कहा कि देश के किसानों के सम्मान में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया यह निर्णय सराहनीय है। यह किसानों की सरकार है। भाजपा के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है।

यह जीत अधूरी: शिवकुमार

शिवकुमार शर्मा ने कहा कि यह किसानों की संघर्ष की जीत है। 700 किसान बलिदान दे चुके हैं। पूरे देश में इन तीनों कृषि कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं। यह कानून किसानों के हित में कतई नहीं थे। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है कि संवैधानिक प्रक्रिया की पूर्ति करते हुए कानूनों को रद्द किया जाएगा। यह किसान आंदोलन की जीत है, लेकिन यह तब तक अधूरी है जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज की खरीद का कानून नहीं बन जाता है।

गुरुपर्व के शुभ दिन पर की गई आज की घोषणा पीएम में करुणामयी राजनीति को दर्शाती है। हमारे पीएम ने हमेशा हम सभी को देश के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सामूहिक रूप से काम करने के लिए प्रेरित किया है। मोदी जी का इरादा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार और उनकी सामाजिक स्थिति को मजबूत करने का है। उनका एकमात्र उद्देश्य अंत्योदय है।

शिवराज सिंह चौहान, सीएम

पिछले 1 साल से अधिक समय से देश भर के लाखों किसान भाई सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की गुहार लगा रहे थे। तीनों कानून वापस लेना यह किसानों की जीत है। इस आंदोलन के दौरान 600 से अधिक किसानों की मौत हो गई। किसानों को प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है, हम स्वागत करते हैं।

कमलनाथ, पूर्व सीएम

कुछ किसान संगठनों ने किसानों को भड़काया था। इसके पक्ष में पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश के कुछ किसान नहीं थे और किसान संगठनों ने भी उन्हें भड़काया था। इस कारण प्रधानमंत्री मोदी को यह फैसला लेना पड़ा है। मगर मेरा दावा है कि मध्य प्रदेश के किसान प्रधानमंत्री के साथ हैं। मोदी जी ने पुनः साबित किया है कि वो किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

एमएसपी की गारंटी मिलती तो होती खुशी

मप्र में इस आंदोलन का असर ज्यादा नहीं था। कानूनी वापसी पर छिंदवाड़ा के किसानों ने पूछा है कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों का क्या होगा। किसान ने कहा कि पीएम देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। इसके साथ ही कहा कि पीएम मुझे कहीं से भी दुरदर्शी नजर नहीं आते हैं। इस जीत का श्रेय शहीद किसानों को है। किसानों ने एक साल तक इसे लेकर आंदोलन किया है। शहीद किसानों को इसका श्रेय मिलना चाहिए। छिंदवाड़ा के दूसरे किसान ने कहा कि यह पूरे भारत के किसानों की जीत है। सेठ-साहूकारों के गुलाम होने से देश का किसान बच गया है। वहीं, एमएसपी को लेकर किसान ने कहा कि सरकार उसकी गारंटी नहीं दे रही थी। अगर सरकार एमएसपी की गारंटी देती तो किसानों को भारी खुशी होती। हमें किसान सम्मान निधि की राशि नहीं देती, मगर एमएसपी की गारंटी देती।

कानूनों की वापसी से खुश नहीं शिवपुरी के किसान

कृषि कानूनों की वापसी पर देश के किसानों की अलग-अलग राय है। मप्र के शिवपुरी जिले के कुछ किसान इस फैसले से खुश नहीं हैं। जिले के दरौनी गांव के किसानों से **जागत गांव हमार** की टीम ने बात की है। किसान दारा सिंह रावत ने कहा कि इस कानून से फायदा यह था कि पूरे देश में किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है। किसान ने कहा कि इसमें कोई एजेंट नहीं था। किसानों का इसका सीधा फायदा होता था। बिल वापसी से फायदा नहीं हुआ है। मोदी को इस पर डटे रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसान किसी पार्टी से मिले हुए थे। दारा सिंह रावत ने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शन कर लोग किसान नहीं। उन्होंने कहा कि किसान नेतागिरी करेगा कि अपनी फसल की देखभाल करेगा। दूसरे किसान ने भी कहा कि कृषि कानून को वापस लेना गलत है। पीएम ने जो कानून बनाया था, वह सही था। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने गलत किया है। पीएम मोदी को फिर से इस पर विचार करना चाहिए।

मध्यप्रदेश को बड़ी मिलेगी राहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए संकेत

अगले महीने हो सकता है केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का भूमिपूजन

प्रदेश के आठ जिलों के किसानों को मिलेगा पानी

भोपाल। विशेष संवाददाता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे के बीच मध्यप्रदेश के लिए एक और राहत की खबर आई है। महोबा में अर्जुन सहायक योजना के लोकार्पण के बीच मोदी ने संकेत दिए कि पिछले 15 साल से अटकी केन-बेतवा लिंक परियोजना का काम जल्द शुरू हो जाएगा। इससे नॉन मानसून सीजन (नंवबर से अप्रैल के बीच) में मध्यप्रदेश को 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर व यूपी को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा।

इस योजना से सागर-विदिशा समेत एमपी के 8 जिलों को पानी पहुंचाना है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा। परियोजना को लेकर मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के बीच चल रहा विवाद केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद 8 महीने पहले सुलझ गया था। दरअलसल, यूपी में चुनाव से पहले नदी जोड़ो अभियान के तहत देश की पहली केन-बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। इसका भूमिपूजन अगले माह झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराने की तैयारी है। इससे पहले शिवराज कैबिनेट दोनों राज्यों और केंद्र के बीच हुए समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।

पलायन रोकना लक्ष्य

प्रधानमंत्री ने महोबा में कहा कि केन-बेतवा लिंक का समाधान भी हमारी ही सरकार ने निकाला है। सभी पक्षों से संवाद करके रास्ता निकाला है। हम बुंदेलखंड से पलायन को रोकने के लिए इस क्षेत्र को रोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

35,111 करोड़ की परियोजना

इसी साल विश्व जल दिवस पर 8 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस एमओए पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मप्र के सीएम शिवराज सिंह चौहान और उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने हस्ताक्षर किए। 35,111 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना में 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि शेष 5-5 प्रतिशत हिस्सेदारी मप्र व यूपी वहन करेंगे।

सालाना 10.62 लाख हेक्टेयर होगी सिंचाई

प्रोजेक्ट के पहले फेज में केन नदी पर ढोढ़न गांव के पास बांध बनाकर पानी रोका जाएगा। यह पानी नहर के जरिया बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा। वहीं, दूसरे फेज में बेतवा नदी पर विदिशा जिले में 4 बांध बनाए जाएंगे। इसके साथ ही बेतवा की सहायक बीना नदी जिला सागर और उर नदी जिला शिवपुरी पर भी बांधों का निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट के दोनों फेज से सालाना करीब 10.62 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही, 62 लाख लोगों को पीने के पानी के साथ 103 मेगावाट हाइड्रो पावर भी पैदा किया जाएगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना में दो बिजली प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 72 मेगावाट है।

12 जिलों को मिलेगा फायदा

परियोजना से बुंदेलखंड के उप्र और मप्र के 12 जिलों को पानी मिलेगा। मप्र के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी को पानी मिलेगा। वहीं, उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों को राहत मिलेगी।

यह थी विवाद की जड़

वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश को रबी फसल के लिए 547 एमसीएम और खरीफ फसल के लिए 1153 एमसीएम पानी देना तय हो गया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश की मांग पर रबी फसल के लिए 700 एमसीएम पानी देने पर सहमति बन गई थी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को 788 एमसीएम पानी देना तय कर दिया था, लेकिन यूपी सरकार ने जुलाई 2019 में 930 एमसीएम पानी मांग लिया था, जिसे मप्र ने इनकार कर दिया था।

2005 में गौर-मुलायम ने किए थे हस्ताक्षर

परियोजना में पानी के बंटवारे को लेकर वर्ष 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की मौजूदगी में दोनों प्रदेशों के बीच अनुबंध हुआ था। तब मप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। तब परियोजना का डीपीआर तैयार नहीं हुआ था। अब डीपीआर तैयार है। इस कारण पानी की भराव क्षमता में कुछ बदलाव हुआ है। इस कारण से तीनों सरकारों के बीच संशोधित एमओए पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।

गांवों को 60 साल बाद मिली आजादी

-अब एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा

भोपाल। अभिनेत्री कंगना रनोट के बाद अब मप्र के कृषि मंत्री कमल पटेल ने आजादी पर बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि देश में गांवों को आर्थिक आजादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाई है। उन्होंने कहा कि आजादी अलग-अलग तरह की होती है- राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक। हमारे देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को ही मिली, लेकिन ये राजनीति और स्वतंत्रता की आजादी है। कुछ आजादी 60 साल बाद भी हमें नहीं मिली। ऐसी आजादियां हमें 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद मिलीं। गांवों को आर्थिक आजादी 24 अप्रैल 2021 को तब मिली, जब प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। दरअसल, कृषि मंत्री एक दिवसीय दौरे पर होशंगाबाद आए थे। कंगना रनोट के आजादी पर दिए गए बयान पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कंगना के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कंसते हुए आजादी के अलग-अलग प्रकार बताए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नकली गांधी बनकर देश पर राज किया और भ्रष्टाचार दिया। देश में अगर कोई सच्चा गांधीवादी है तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 60 साल में कांग्रेस ने गरीबों को शौचालय, आवास नहीं दिए। गरीबों को यह सब हमारी सरकार में मिल रहा है। हमारी सरकार गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है।

-कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह जिले में अब सड़क पर नहीं दिखेंगी गाय

हरदा में 20 गौशाला निर्माणाधीन, गाय संरक्षण पर फोकस

हरदा। संवाददाता

जिले में गोमाताओं को सुव्यस्थित स्थान पर सभी सुविधाओं के साथ रखने के लिए गौशालाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन गौशालाओं के निर्माण गति धीमी होने के कारण गाय सड़ेक पर बैठी मिल रही हैं। इसके कारण यातायात प्रभावित हो रहा है।

इसके साथ ही हादसों की आशंका भी बनी रहती है। जिले में 18 नई गौशालाओं का निर्माण चल रहा है, जबकि दो गौशालाओं में विस्तारीकरण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जिले में तीन शासकीय गौशालाओं का निर्माण पूर्व में पूर्ण हो चुका है। इसमें ग्राम मगरधा, नीमसराय एवं छिदगांव मेल में गौशाला संचालित हो रही है। जिसमें करीब 290 गायों को रखा जा रहा है। गाय के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण पशुपालन विभाग के अमले द्वारा किया जाता है। जिले में जनसहयोग से नौ गौशाला संचालित की जा रही हैं। जहां पर गायों की सेवा की जा रही है। इसके साथ ही यहां पर दानदाताओं से मिलने वाले दान से गौशालाओं में व्यवस्थाएं की जा रही है। जिले में नौ गौशाला जनसहयोग एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही हैं। गौशाला के संचालन के लिए समितियां भी बनाई गई हैं। इसके माध्यम से गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है।

गौशाला के लिए 7.26 करोड़ मंजूर

जिले में 20 गौशालाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें से ग्राम पंचायत साल्याखेड़ी की चीराखान और हंडिया ग्राम पंचायत की गौशाला में विस्तारीकरण कार्य किया जा रहा है। जिले की 20 गौशालाओं के लिए 7.26 करोड़ की राशि स्वीकृति की गई। जबकि अब तक करीब 2.15 करोड़ राशि खर्च की चुका है। गौशालाओं के निर्माण के लिए एजेंसी ग्राम पंचायत हो बनाया गया है।

यहां बन रही गौशाला

जिले में 20 गौशाला निर्माणधीन हैं। इसमें से दो में विस्तारीकरण कार्य किया जा रहा है। जबकि 18 गौशालाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसमें ग्राम रातातलाई, सोनतलाई, डगावाशंकर, कुकरावद, धनवाड़ा, बारंगा, सक्तापुर, जामुखो मगरया, पीपल्या, गोमगांव, काल्याखेड़ी, जामन्याखुर्द, हसनपुरा, छिदगांव तमोली, नजरपुरा, छीरपुरा, कपासी शामिल हैं।

इनका कहना है

जिले में तीन गौशालाओं संचालित है। इसमें करीब 290 गाय हैं। जिनका संचालन ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। इसमें ग्राम नीमसराय, मगरधा, छिदगांव मेल की गोशाला शामिल हैं। जिले में 18 गौशालाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं दो गौशालाओं में विस्तारीकरण कार्य किया जा रहा है।

-पंकज दुबे, अतिरिक्त उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवा, हरदा

प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के साधन की तलाश में जुटी राज्य सरकार

चंदन की खेती से महकेगा अपना मध्यप्रदेश

-पीएम ने दिखाई राह, शिवराज सरकार ने शुरू किया विचार, पहले लगाया जा रहा उचित संभावनाओं वाले हिस्से का पता

भोपाल। प्रशासनिक संवाददाता

परंपरागत खेती में उत्पादन के चरम पर स्थान बना चुका मध्य प्रदेश अब किसानों की आमदनी बढ़ाने के दूसरे साधन भी तलाश रहा है।

किसानों को बांस, औषधीय पौधों सहित दूसरी फसलों की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे में ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चंदन की खेती की राह दिखाई और राज्य सरकार ने इस पर विचार भी शुरू कर दिया है। फिलहाल यह देखा जा रहा है कि प्रदेश के किस हिस्से में अच्छी किस्म का चंदन लगाया जा सकता है। उचित संभावनाओं का पता लगाने के बाद चंदन की खेती की योजना तैयार की जाएगी। यह जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी जा सकती है। गौरतलब है कि देश में चंदन का उत्पादन कम है और बाजार में मांग ज्यादा। यही कारण है कि चंदन महंगा बिकता है और इसकी खेती करवाकर किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है।

सुरक्षा पर फोकस

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिले थे। इस दौरान चौहान ने उन्हें विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी तो प्रधानमंत्री ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए चंदन की खेती पर ध्यान देने को कहा था। इसके बाद से मुख्यमंत्री भी दो बार अपनी जनसभाओं में चंदन की खेती को विकल्प के रूप में अपनाने की बात कर चुके हैं। राज्य सरकार चंदन की सुरक्षा को लेकर भी प्रबंध पर विचार कर रही है, क्योंकि चंदन की लकड़ियों की चोरी भी खूब होती है।

प्रदेश में 11 हजार 490 पेड़

प्रदेश में भोपाल, सीहोर, सागर सहित मालवा अंचल के कई जिलों में चंदन के 11490 पेड़ हैं। इनमें से 3,990 रीवा और 7,500 सागर जिले में हैं। सीहोर जिले में चंदन का छोटा जंगल है। सिवनी जिले के लखनादौन के पास वन विभाग और कटनी में किसानों ने प्लांटेशन किया है। मालवा अंचल में भी किसानों ने अपने खेत और खलिहानों पर चंदन के पेड़ लगा रखे हैं। इनमें से ज्यादातर पेड़ रक्त चंदन (लाल चंदन) के हैं, पर अच्छी किस्म का न होने के कारण यह ऊंचे दामों में नहीं बिक पाता है।

दूसरी फसल भी लेंगे किसान

किसान खेत में चंदन के साथ अन्य फसल भी उगा सकते हैं। इसलिए उन्हें नियमित आमदनी के लिए लंबे समय तक इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। जब तक चंदन लाभ देने की स्थिति में आएगा, तब तक दूसरी फसलों से गुजारा चलता रहेगा। चंदन के पौधे की आठ साल तक चोरी का भी डर नहीं है। तब तक इसमें सुगंध नहीं आती है। सामान्य तौर पर एक चंदन के पेड़ से 15 से 20 किलो लकड़ी निकलती है।

सीएम बोले- गौ-ग्रास के लिए टैक्स की योजना बनाएं

मप्र में अब गाय-टैक्स!

- » गौ-अभयारण्य को गौ-पर्यटन का केन्द्र बनाया जाएगा
- » सालरिया गौ-अभयारण्य को आदर्श अभयारण्य बनाया जाएगा
- » सरकारी कार्यालयों में किया जाएगा गौ-फिनायल का उपयोग
- » जबलपुर के गंगईवीर में गौवंश वन विहार की होगी स्थापना

भोपाल। विशेष संवाददाता

गौ संरक्षण के लिए मध्यप्रदेश सरकार गाय टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों को निर्देश दिए कि गौ-ग्रास के लिए टैक्स लगाने की योजना बनाएं। इसके साथ ही जन-भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाए। गौरतलब है कि इसी तरह का टैक्स लगाने का मसौदा कमलनाथ सरकार में भी अफसरों ने तैयार किया था। शिवराज सरकार भी ऐसे ही विकल्पों के जरिए गायों के भरण-पोषण की तैयारी कर रही है। फर्क इतना है कि कमलनाथ सरकार महंगी कारों, स्टांप डयूटी और टोल प्लाजा की फीस बढ़ाकर गौशालाओं का निर्माण करना चाहती थी, लेकिन शिवराज सरकार गायों के चारे-भूसे की स्थाई व्यवस्था करने

बंद गौ-सदन खुलेंगे

सीएम ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यालय में गौ-फिनायल का उपयोग किया जाए। आगर मालवा जिले के सालरिया गौ-अभयारण्य को देश के आदर्श के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में 20वीं पशु संगणना के अनुसार एक करोड़ 87 लाख 50 हजार गौवंश हैं। प्रदेश में बंद किए गए आठ गौ-सदन फिर से प्रारंभ किए जाएंगे। बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

गौ-कैबिनेट में होगा मंथन

कमलनाथ सरकार ने गौशालाएं खोलने के लिए धन जुटाने वन, राजस्व, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिवों की कमेटी का गठन किया था, जबकि शिवराज सरकार में मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक सहमति के बाद गायों को पालने के लिए सेस लगाने पर गौ-कैबिनेट की बैठक में विचार होगा। इस समय राज्य में 1300 गौशालाएं हैं, जिनमें 1.80 लाख गायों को रखा गया है। बताया जाता है कि पिछली कमलनाथ सरकार ने बजट में प्रति गाय 20 रुपए का आवंटन किया था। पिछले वित्तीय वर्ष में पशुपालन विभाग का बजट 132 करोड़ रुपए रखा था, जबकि 2020-21 में तो यह सीधे 11 करोड़ रुपए हो गया, यानी लगभग 90 फीसदी की कटौती कर दी गई। यानी प्रति गाय सरकारी खुराक 20 रुपए से घटकर 1 रुपए 60 पैसे हो गई।

जबलपुर में गौ-वंश वन विहार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गौ-शालाओं के विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को कार्य दिया जाए। स्वयंसेवी संगठन सेवाभाव रखकर गौ-शालाओं को अच्छी तरह विकसित कर सकते हैं। उन्होंने अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित गौ-शालाओं को अनुदान देने तथा प्रदेश की 6 गौ-शालाओं को प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जबलपुर जिले के गंगईवीर में गौ-वंश वन विहार की स्थापना करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंगईवीर में पशुपालन विभाग की 530 एकड़ भूमि में क्रमबद्ध तरीके से दो हजार गो-वंश को आश्रय दिया जा सकेगा।

नस्ल सुधार के हों प्रयास

प्रदेश में गौ-वंश एवं नंदी की नस्ल सुधार के विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने गौ-उत्पादों के विक्रय के लिए विशेष व्यवस्था बनाने एवं अधिकाधिक प्रचार-प्रचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौ-फिनायल का उपयोग शासकीय कार्यालयों में किया जाए। प्रदेश में 2200 गौशालाएं बनाई जाएंगी। इनके संचालन समाजसेवी संस्थाओं को सौंपा जाएगा। गौ-अभयारण्य को गौ-पर्यटन का केन्द्र बनाया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है। प्रदेश में बंद किए गए 8 गौ-सदन पुन: प्रारंभ किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मंडी बोर्ड आदि से प्राप्त राशि एवं व्यय की गई राशि का अनुमोदन किया।

पीएम स्वनिधि योजना में मध्यप्रदेश अव्वल

तेलंगाना दूसरे व उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर

खेमराज मौर्य, शिवपुरी।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 101.60 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित कर मध्यप्रदेश देश में अव्वल है। केन्द्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा इस योजना में मध्यप्रदेश को वर्ष 2021-22 के लिए 4 लाख 5 हजार पथ-विक्रेताओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया गया था। लक्ष्य के विरुद्ध मध्यप्रदेश में 4 लाख 11 हजार 481 पथ-विक्रेताओं को 10-10 हजार रुपए ब्याज रहित ऋण वितरित किया जा चुका है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रथम चरण के साथ ही द्वितीय चरण में भी मध्यप्रदेश नंबर एक है। उन्होंने कहा है कि समय पर 10 हजार रुपये का ऋण चुकाने वाले पथ-विक्रेताओं को 20 हजार और फिर 50 हजार रुपए का ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान योजना में है। आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में देश में तेलंगाना द्वितीय, उत्तर प्रदेश तृतीय, आंध्र प्रदेश चतुर्थ, कर्नाटक 5वें और छत्तीसगढ़ छठवें स्थान पर है।

खेती के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएं

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में खेती के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए पूरी मुस्तैदी से कार्य करें। किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किए जाएं। जैविक खेती एवं दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। हाल ही में मुख्यमंत्री मंत्रालय में आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमेप अंतर्गत गठित मंत्री समूह की अंतर्विभागीय बैठक ले रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादों का अधिकाधिक निर्यात करने के लिए उत्पादन को बढ़ाएं। जैविक खेती के लिए माहौल तैयार कर किसानों को प्रोत्साहित करें। फसलों के उत्पादन एवं विक्रय के लिए गंभीरता से प्रयास करें। फसलों के विविधीकरण एवं सामाजिक वानिकी जैसे माध्यमों से उत्पादन को बढ़ाया जाए।

भविष्य का पशु है बकरी

डॉ. सत्येन्द्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी (म.प्र.)

पुरातन काल से ही बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। एक दौर था कि जब गरीब की झोपड़ी के बाहर उसकी चारपाई से बकरियों का बंधा होना एक आम बात थी, लेकिन समय के बदलते दौर के साथ बकरी पालन के तौर तरीकों में कुछ बदलाव जरूर आया है। बावजूद इसके आज भी ग्रामीण अंचल में बकरी पालन के तौर तरीके लगभग वही पुराने ही चले आ रहे हैं। समय के बदलाव और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आज बकरी पालन के तरीकों में वैज्ञानिक तकनीकी बातों का समावेश किया जाना आवश्यक हो गया है। इसकी अनदेखी करने पर बकरी पालन से हम अच्छा मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि बकरी पालन के सही तरीके अपनाकर अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। पिछले कुछ दशकों से भारत में बकरियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बकरी पालन आज एक व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। अत: जरूरत इस बात की है कि बकरी पालन को पूर्णत: वैज्ञानिक ढ़ग से किया जाए।

बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है, जो कि कम समय में, कम श्रम एवं कम पूंजी लगाकार शुरू करके अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। क्योंकि बकरी एक छोटा जानवर है, जो कि बच्चा पैदा करने के लिए जल्दी तैयार हो जाता है। बकरियों की कई प्रजातियां ऐसी हैं, जो कि एक साल में दो बार तक बच्चा देकर हर बार दो-दो बच्चे पैदा करने की क्षमता रखती हैं। बकरी आवास के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। यह घास-फूस, पेड़-पौधों की पत्तियां आदि खाकर हर प्रकार की जलवायु में अपने आप को ढालने की क्षमता रखती हैं। देश में क्षेत्र विशेष की जलवायु के अनुकूल बकरियों की ऐसी नस्लें पाई जाती हैं,जो कि राजस्थान के रेगस्तिान में 55 डिग्री सेंटीग्रेट लेकर लेह-लद्दाक की वर्फीली पहाड़ियों में -20 डिग्री सेंटीग्रेट तक के तापमान में अपने आपको ढालने की क्षमता रखती हैं। बदलते जलवायु परिवर्तन और देश में बकरी मांस और दूध की बढ़ती मांग को देखते हुए बकरी को एक भविष्य का पशु कहना कदाचित गलत नहीं होगा। अत: हमें बकरी पालन शुरू करते समय अपने क्षेत्र विशेष की जलवायु के अनुरूप उपलब्ध नस्ल को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। वर्तमान में देश में बकरियों की कुल 27 प्रजातियां पायी जाती हैं। उत्पादन के अनुसार बकरियों को क्रमश: दुग्ध, मांस और रेशा उत्पादक नस्लों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा बकरियों की नस्लों को क्षेत्र विशेष की जलवायु के अनुकूल भी विभाजित किया गया है। अत: हम अपनी आवश्यकता और बाजार की मांग के अनुरूप नस्ल का चुनाव कर सकते हैं।

बकरियों का पालन तीन पद्धतियां के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें क्रमश: सघन पद्धति/इंटेंसिव मेथर्ड, अर्ध सघन पद्धति/सेमी इंटेंसिव मेथर्ड तथा मुक्त विचरण पद्धति/एक्सटेंसिव मेथर्ड प्रमुख हैं। प्रथम पद्धति के अंतर्गत बकरियों को घर अथवा फॉर्म पर रखकर ही पाला जाता है। इस पद्धति में बकरियों को चारागाह चरने नहीं भेजा जाता है। इस तरीके से बकरियों से उनकी क्षमता के अनुरूप उत्पादन लिया जा सकता है। दूसरी पद्धति में बकरियों को चारागाह में चराने के साथ-साथ घर अथवा फॉर्म पर अलग से चारा दाना भी खिलाया जाता है। क्योंकि आज चारागाह सीमित होने के कारण बकरियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है। तीसरी पद्धति में बकरियों को पूरी तरह से केवल चारागाह में चराकर ही पालन किया जाता है। इस पद्धति में कम श्रम की जरूरत होती है, लेकिन उत्पादन क्षमता भी काफी गिर जाती है। इसलिए बदलते दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन के लिए अर्ध सघन पद्धति सबसे अच्छी मानी गयी है, क्योंकि चारागाह में चराने ले जाने पर जानवरों का व्यायाम भी हो जाता है और पौषण की अतिरिक्त पूर्ती घर पर खिलाकर कर दी जाती है, जिससे जानवरों से अच्छा

उत्पादन प्राप्त होता रहता है। बकरी पालन में आवास प्रबंधन का महत्वपूर्ण स्थान है। बकरियों का आवास मौसम के प्रतिकूल प्रभाव और जंगली जानवरों से रक्षा करने के साथ-साथ आरामदायक होना चाहिए। उसमें हवा, प्रकाश, और पानी के निकास का समुचित प्रबंध होना चाहिए। बकरियों की संख्या के अनुरूप आवास छोटा या बड़ा बनाया जा सकता है। बाड़े की लंबाई की दिशा पूर्व-पश्चिम रखनी चाहिए। बकरी आवास के लिए हमेशा ऊंची जगह का चयन करना चाहिए। एक आदर्श बकरीशाला के लिए लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर किनारों पर ऊंचाई 2.7 मीटर तथा मध्य में ऊंचाई 4 मीटर रखनी चाहिए। बकरी आवास बनाने में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके लागत कम की जा सकती है। बकरीशाला में मेमनों, गर्भवती बकरियों, बकरों आदि के बाड़े अलग-अलग रखना चाहिए। बकरीशाला के आसपास पेड़-पौधों का होना बहुत जरूरी होता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में हरियाली बनी रहे। बकरियों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए 3 से 4 घंटे चराने के अलावा उन्हें घर पर अलग से चारा दाना खिलाया जाना जरूरी है। खासकर गर्भवती एवं दूध देने वाली बकरियों व मांस वाले बकरों को अतरिक्त रूप से आहार देना चाहिए। इस के लिए 100 किग्रा शरीर भार पर 3 से 4 किग्रा शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसके लिए 1 से 2 किग्रा हरा चारा तथा शेष अरहर, चना, मटर आदि के भूसे की व्यवस्था करना चाहिए। वैज्ञानिक संस्तुति के अनुसार शरीर वृद्धि के लिए 200 ग्राम, प्रजनन काल से एक माह पूर्व 300 से 400 ग्राम, गर्भ के अंतिम माह से 300 से 400 तथा दुग्ध उत्पादन के लिए 400 से 500 ग्राम प्रति किग्रा दुग्ध उत्पादन पर आहार देना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि बकरियों का राशन संतुलित होना बहुत जरूरी है। बकरी पालक दली हुई मक्का-48 किग्रा, मूंगफली/सरसों की खली-20 किग्रा, गेहूं की चोकर-22 किग्रा, गुड़-7 किग्रा, खनिज लवण मिश्रण-2 किग्रा एवं साधारण नमक-1 किग्रा के अनुपात में मिलाकर 100 किग्रा संतुलित राशन तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखें कि राशन शुद्ध, साफ और कीटाणु रहित होना चाहिए। बकरी पालन से अच्छा लाभ लेने के लिए बकरियों का बीमारियों से बचाव करना जरूरी हो जाता है। इसके लिये स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र को अपनाना बेहतर रहता है। विशेषकर मेमनों को निमोनियां, दस्त कोक्सीडियोसिस तथा आंत्रशोध का प्रकोप जल्दी होता है। इनसे बचाव के लिए बाड़े की मिट्टी का उपचार एवं चारे दाने की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। बकरियों को संक्रामक रोगों से बचाव के लिए समय-समय पर रोगरोधी टीके लगवाते रहना चाहिए। यह टीके निकटतम राजकीय पशु चिकित्सालय से लगवाए जा सकते हैं। बकरियों में मुख्यत: खुरपका-मुहंपका, बकरी प्लेग अथवा पीपीआर 6-पेस्टीडेस पेस्टिस रूमीनेंट्स-8, निमोनियां, चेचक, इन्ट्रोटोक्सीमिया या आंत्र विषाक्तता, जोन्स डिजीज, गलघोंटू, ब्रूसेल्लोसिस या गर्भपात आदि संक्रामक बीमारियां होती हैं। काक्सीडियोसिस से बचाव के लिए 1 से 2 माह की उम्र पर काक्सीमारक दवा मोनेंसिन-20 ग्राम/100 किग्रा दाना मिश्रण में मिलाकर 6 माह की उम्र तक खिलाना चाहिए। कृमि रोगों में अंत: परजीवी इंडोपैरासाइट्स से बचाव के लिए 3 माह की उम्र में पहली बार तथा फिर हर चार माह के अंतर पर सभी बकरियों को कृमिनाशक दवा देते रहना चाहिए।

गैर दलहनी फसलों का अधिक उत्पादन के लिए एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक एक कारगर उपाय

आशुतोष मिश्र
मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन, कृषि संकाय, म.गां.चि.ग्रा.विवि, चित्रकूट, सतना, मप्र,

पौधों के वृद्धि एवं विकास तथा उनके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए कुल 17 तत्वों की जरूरत होती है। इसमें नाइट्रोजन मुख्य पोषक तत्वों के रूप में काम करता है। क्योंकि ये पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए किसान सबसे अधिक खेतों में नत्रजनधारी रासायनिक उर्वरकों में यूरिया का ही प्रयोग करते हैं। इनके बढते हुए मांग के कारण दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं। कभी-कभी समय पर भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जैव उर्वरक की खोज करके फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करना आर्थिक दृष्टि कोण से बहुत ही उपयोगी कार्य है। दलहनी फसलों जैसे चना, मटर, मसूर, अरहर, मूंग, उड़द और लोविया आदि में जैव उर्वरक बहुत प्रचलित हो चुका है, लेकिन धान व अन्य फसलों में इन जैव उर्वरक का प्रचलन ना के बराबर है। इस दिशा में सर्वप्रथम 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैजरीन्क नामक सोवियत वैज्ञानिक ने एजोटोबैक्टर नामक जीवाणु को मिट्टी से अलग कर इनकी गुणवत्ता एवं क्रियाशीलता का पता लगाया और इस कार्य को आगे बढ़ाया। एजोटोबैक्टर क्रोकोकम भारतीय मृदाओं में पायी जाने वाली प्रमुख जीवाणु है, जो भूमि में एवं पौधों की जड़ों की सतह पर स्वतंत्र रूप में रहते हैं। ये विविध पोषी होते हैं। ये जीवाणु आक्सीजन की उपस्थिति में वायु मंडलीय नत्रजन को अमोनियां में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते रहते हैं। एजोटोबैक्टर जीवाणु प्रत्येक किस्म के गैर दलहनी फसलों में उपयोग किया जा सकता है। एजोटोबैक्टर जीवाणु युक्त कल्चर का प्रयोग निम्नांकित फसलों में सफलता पूर्वक नत्रजन की उपलब्धता के लिए किया जा सकता है। धान्य फसलें- गेहूं, जौ, धान, ज्वार, मक्का, बाजरा व जई आदि। तिलहनी फसलें- सरसों, तिल, तोरिया एवं सूर्यमुखी आदि। नगदी फसलें- गन्ना, कपास, तम्बाकू, जूट आदि। सब्जियां- आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर, बैगन, गोभी व मिर्च आदि। बागवानी फसलें-केला, अंगूर, पपीता आदि। एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक की उपलब्धता हमारे देश के कृषि विवि, राष्ट्रीय, कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र (भारत सरकार का उपक्रम) गाजियाबाद उप्र से प्राप्त किया जा सकता है। एजोटोबैक्टर ठोस एवं द्रव दोनो रूप में उपरोक्त संस्थाओं एवं बाजार में उपलब्ध है। किसान अपनी सुविधा के अनुरूप किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। 500 ग्राम का एक पैकेट या 500 मिली तरल एजोटोबैक्टर प्रति एकड़ एक बोरी यूरिया के बराबर नत्रजन स्थापित करता है। खेतों में जैविक पदार्थों की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी अधिक नाइट्रोजन स्थापित करता है। हमारे देश के विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसेधानों से ज्ञात हुआ है कि फसल की उपज 11 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है। एजोटोबैक्टर तरल जैव उर्वरक को 500 मिली प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। खेतों की फसलों में एजोटोबैक्टर कल्चर का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित विधिया अपनायी जा सकती हैं। बीज की मात्रानुसार तरल जैव उर्वरक को 1 से 2 लीटर पानी में घोल बनाएं। इस जैव उर्वरक के घोल को 15 से 20 मिनट तक बीज में मिलाएं। जिससे बीज की सतह पर जैव उर्वरक की एक परत चढ़ जाए। इस उपचारित बीज को छाया में लगभग 45 मिनट तक सुखाएं। उपचारित बीज की तुरंत बोवनी करें। तरल एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक को 50-100 किलो कम्पोस्ट में अच्छी तरह मिलाकर पौध रोपड या बीज के बोवनी के पूर्व खेत में समानरूप से विखेरना चाहिए। शाम के समय प्रयोग करना उचित होगा। यदि तरल जैव उर्वरक का प्रयोग बोने के समय नहीं हो पाया है तो खड़ी फसल में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य सिचाई की अवस्था में जिस खेत में पानी का बहाव होता है। उसी स्थान पर तरल जैव उर्वरक का घोल एक उचित पात्र में रखकर धीरे-धीरे पानी में मिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ड्रिप सिचांई के माध्यम से भी तरल जैव उर्वरक की उचित मांग उचित मात्रा पानी के टैंक में मिलाकर ड्रिप सिचांई से डालें। तरल जैव उर्वरक को तेज धूप एवं गर्मी से दूर रखना चाहिए। तरल जैव उर्वरक को फसलों पर छिड़काव न करें, क्योंकि ये धूप एवं गर्मी के प्रति संवेदनशील होता है। तरल जैव उर्वरक को नम स्थानों पर रखें ताकि जीवाणु अधिक समय तक जीवित रहें। तरल जैव उर्वरक को बच्चों एवं पालतू जानवर से दूर रखें। जैव उर्वरक के उपयोग के बाद साबुन से हाथ धोना जरूरी है। जैव उर्वरक को अन्य रसायन उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि दवाओं के साथ न मिलाएं। यदि मिलाया जाता है तो जीवाणु मर सकते है। तथा वांछित परिणाम प्राप्त नही हो सकतें।

भूमि, जल अरू वायु है, खेती के आधार।
रखना इन्हें संभाल कर कृषकों खूब विचार।।

बुंदेलखंड का गौरव, हीरों की चमक और विकास का संघर्ष

पुरातन काल से समृद्ध और परिपूर्ण बुंदेलखंड अपने विकास के लिए फिर से संघर्ष कर रहा है। इस दफा विकास के मंच पर है बुंदेलखंड की रत्नगर्भा वसुंधरा जो कि सदियों से अपने अंदर एक से एक नायाब हीरों को संजोती आई है। फिर चाहे वो शूरवीर महाराजा छत्रसाल हों या दैदीप्यमान मनीषी ऋषि विश्वामित्र। चर्चा है मप्र के छतरपुर जिले में स्थित बक्सवाहा तहसील में मिले हीरों के भंडार की। जैसा कि हीरा अपने नाम से चिर-परिचित है, जिन्होंने निकाले जाने के पहले ही अपनी चमक ऐसी फैलाई है कि इसके तेज ने वाद-विवाद का एक नया संग्राम खड़ा कर दिया है। एक तरफ इन्हें निकालने के लिए 2.15 लाख पेड़ काटे जाने का विरोध और वन संपदा की दुहाई, वहीं दूसरी ओर दशकों से विकास और सुविधाओं की राह देखता बक्सवाहा और छतरपुर जिला। इस रस्साकसी के बीच दोनों पक्ष मजबूती से अपनी बात लेकर लामबंद हैं। अतीत के पन्नों पर अगर नजर दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि बुंदेलखंड तपस्वियों और वीरों की भूमि रही है,जो समय आने पर अपने अधिकार के लिए प्राणोत्सर्ग करने तक से किंचित भयभीत नहीं हुए। अपने गौरव, सम्मान, संपदा, संस्कृति और अधिकारों के लिए संघर्ष करने में श्लेष मात्र भी संशय नहीं किया। ऋषि विश्वामित्र, द्वैपायन व्यास, ऋषि वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास, आचार्य केशवदास, ईसुरी, ऋषि अगस्त्य, महाराजा छत्रसाल, वीरांगना लक्ष्मी बाई, वीरवर लाला हरदौल, राजा गंड, मदनपाल, वीर सिंह जूदेव, झलकारी बाई और आचार्य चाणक्य इत्यादि की रचनाओं और शौर्य से यह भूमि तपोभूमि और वीरभूमि मे परिपूर्ण हुई है। बुंदेलखंड की जनमानस नें इन्हें अपना गौरव मानकर अपने शीश से लगाकर रखा है। इन रत्नों के साथ पन्ना जिले के बाद छतरपुर जिले की बक्सवाहा तहसील में असली हीरों की खोज हुई है।

28 दिसंबर 2017 को प्रयोगशाला का धूमधाम से किया गया था लोकार्पण

विदिशा में चार साल बाद भी किसान मिट्टी परीक्षण से वंचित

-स्टाफ की कमी से प्रयोगशाला में मशीन रखी हुई धूल खा रहीं

विदिशा। संवाददाता

मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के लिए पहले भूमि उपलब्ध नहीं हो रही थी बाद में कृषि उपज मंडी में भूमि उपलब्ध करा दी और 2017 में कृषि मंडी परिसर के अंदर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बनकर तैयार हो गई। 28 दिसंबर 2017 को 36 लाख रुपए की लागत से बनने वाली मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का विधिवत लोकार्पण भी किया गया।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित प्रदेश के मंत्रियों द्वारा किसानों को सौगात बताकर कहा गया था कि क्षेत्र के किसानों को मिट्टी का परीक्षण कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा उन्हें रायसेन या अन्य स्थानों पर जाने की बचत होगी, लेकिन करीब चार साल बाद एक भी किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण प्रयोगशाला में नहीं हुआ है। क्योंकि स्टाफ की कमी के चलते आज तक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला शुरू ही नहीं हो सकी है। 2-4 मशीन रखी हुई धूल खा रही हैं।

किसानों का समय-पैसा बर्बाद- किसानों को इस बार भी जिला मुख्यालय पर 85 किमी दूर जाकर अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाना पड़ता है।

या फिर सागर जाते हैं। किसान जिला मुख्यालय पर अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराने में जाने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें एक तो 85 किमी दूर जाना पड़ता है और पैसा खर्च होता है और साथ में समय की बर्बादी भी होती है। यदि किसान चले भी जाएं तो उन्हें 1 दिन में मिट्टी जांच की रिपोर्ट नहीं मिल पाती है जिससे उन्हें दो बार चक्कर लगाना पड़ता है। कभी-कभी तीन चार बार भी चक्कर हो जाते हैं तब कहीं जाकर उन्हें मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट मिल पाती है।

इनके नाम की लोकार्पण पट्टिका

28 दिसंबर 2017 को लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में लोकार्पण के लिए जो पत्थर लगाया गया है उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रमुख मंत्रियों में कैबिनेट मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह, उमा भारती, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, कैलाश जोशी, कैलाश सारंग, बाबूलाल गौर, सीताशरण शर्मा, विक्रम वर्मा, प्रभात झा, कैलाश विजयवर्गीय, नंदकुमार सिंह चौहान, जयंत मलैया, गोपाल भार्गव, गौरीशंकर शेजवार, कुसुम मेंहदेले, विजय शाह, उमाशंकर गुप्ता, राजेंद्र शुक्ला, रामपाल सिंह लोक निर्माण मंत्री और भी अन्य के नाम दिए हुए हैं।

36 लाख में बनी इमारत

मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला करीब 36 लाख रुपए की लागत से तैयार हुई। इसकी निर्माण एजेंसी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग है। बावजूद इसके अभी तक प्रयोगशाला शुरू ही नहीं हो सकी है और ना ही स्टाफ नियुक्त किया गया है तो मिट्टी की जांच के लिए मशीने तो दूर की बात है। दो या तीन मशीनें मामूली तौर कि वहां पर रखी हुई धूल खा रही हैं।

-उपज खरीदने बनाया मोबाइल एप, प्रदेश में लागू की व्यवस्था

किसानों की भ्रांतियां दूर कर मप्र ने हासिल की कृषि क्षेत्र में उपलब्धियां

-न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान, मूंग की रिकॉर्ड खरीदी

भोपाल। विशेष संवाददाता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भले ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी हो पर किसानों की भ्रांतियां दूर करते हुए मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान और मूंग की रिकॉर्ड खरीद करने के साथ ही मंडियों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाकर उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए उनसे सीधे अनाज खरीदने की व्यवस्था बनाई है। इससे किसान को मंडी में आने की जरूरत ही नहीं रह गई है। इस माडल को पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया है।

किसान के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो, इसके लिए प्रक्रिया आनलाइन रखी गई है ताकि निगरानी भी होती रहे और मंडी टैक्स की चोरी भी न हो। प्रदेश में यूं तो कृषि कानूनों के विरोध में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ पर सरकार ने किसान हित में एक के बाद एक कई कदम उठाए। इसका लाभ किसानों को मिला और प्रक्रिया भी सुधार हुआ। कोरोना संकट की वजह से किसानों को मंडियों तक उपज बेचने के लिए आना मुश्किल था और उपज नहीं बिकने से किसान परेशान हो जाते, इसलिए समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद की गई।

बनाई उपज खरीदी की व्यवस्था

इस व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए मोबाइल एप के माध्यम से उपज खरीदने की व्यवस्था बनाई। इसमें मंडियों में पंजीकृत व्यापारियों को यह सुविधा दी गई कि वे गांव में किसान के खेत, खलिहान या फिर घर से सीधे उपज खरीद सकते हैं। किसान और व्यापारी के बीच सहमति होने पर व्यापारी एप में किसान की पूरी जानकारी सहित उपज की मात्रा, तय मूल्य आदि की जानकारी भरता है और किसान के पास एसएमएस पहुंचता है। इसके आधार पर आगे की प्रक्रिया होती है। इसी तरह भुगतान के लिए भी एसएमएस मिलता है।

पहली बार खरीदी रिकॉर्ड मूंग

इसी तरह मंडियों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। ग्रेडिंग, शार्टिंग मशीनें लगाने के साथ प्रसंस्करण की इकाईयां निजी क्षेत्र के सहयोग से लगवाने की कार्ययोजना बनाई गई है। दस लाख टन क्षमता के गोदाम बनाए जा रहे हैं ताकि किसान को यदि उपज नहीं बेचना है तो वो उसका सुरक्षित भंडारण कर सकता है। किसानों को ग्रीष्मकालीन मूंग का उचित दाम दिलाने के लिए पहली बार आठ लाख टन से ज्यादा समर्थन मूल्य पर खरीदी गई।

किसानों के हित में एक नहीं कई कदम उठा रहे हैं। हाल ही में 15 हजार करोड का अनुदान सस्ती बिजली देने के लिए किया गया है। सिंचाई क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। कस्टम हायरिंग सेंटर के बाद अब कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर प्रारंभ किए जा रहे हैं। इससे किसान उपज को औने-पौने कीमत में बेचने की जगह प्रसंस्करण करके अच्छी कीमत में बेच सकेगा।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

-प्रदेश में योजना अक्टूबर से अमल में आई

बिजली सब्सिडी किसानों के खाते में सीधे पहुंचेगी

भोपाल। संवाददाता

रसोई गैस की तरह सीधे खातों में बिजली सब्सिडी पहुंचाने की योजना अक्टूबर से अमल में आ गई है। सब्सिडी की राशि किसानों के वचुर्अल खातें में अक्टूबर को पहुंची है। पूर्व क्षेत्र कंपनी के सिवनी जिले के 50 हजार किसानों के लिए यह योजना शुरू हुई है। इसके बाद छिंदवाड़ा जिले में इसकी शुरुआत होगी। लंबे समय से इस योजना का लागू नहीं किया जा पा रहा था। किसानों के काल्पनिक बैंक खाते खुले हैं। ये कंपनी में पहला प्रयोग होगा जिसकी सफलता के बाद इसे दूसरे जिलों में लागू किया जाना है। प्रदेश में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के विदिशा और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के झाबुआ में यह योजना लागू हो चुकी है।

सब्सिडी पहुंची खातों में

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के किसानों को मिलने वाली करीब 90 फीसद सब्सिडी सरकार उनके काल्पनिक खातों में भेजना शुरू किया है। प्रदेश के तीन जिलों में ये पायलेट प्रोजेक्ट लांच हो रहा है। इसमें विदिशा,झाबुआ और सिवनी को शामिल किया गया है। तीनों विद्युत वितरण कंपनी के एक-एक जिलों को लिया गया है। सिवनी में करीब 51 हजार कृषि पंप है। इनकी सब्सिडी भेजी गई है। कंपनी इस प्रयोग के बाद छिंदवाड़ा जिले में यह योजना लागू

काल्पनिक खाते

बिजली कंपनी ने हर किसान के नाम का काल्पनिक खाता खुलवाएगी। पहले पूर्व क्षेत्र कंपनी में एचडीएफसी बैंक को खाते खोलने का जिम्मा दिया था लेकिन किन्ही कारण से खाते नहीं खुल पाए। अब नए सिरे से बैंक का चयन किया जा रहा है। जिनके द्वारा खाते खुलेंगे। किसान को खाते में बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। खाते से लेनदेन में किसानों की किसी तरह की कोई रजामंदी की जरूरत नहीं होगी। इस खाते में सिर्फ सब्सिडी का पैसा पहुंचेगा जो सीधे बिजली कंपनी अपने खाते मे ट्रांसफर होगा। किसान इस खाते से किसी तरह का कोई लेनदेन नहीं कर पाएगा।

देने होंगे ये दस्तावेज

कृषि पंप उपभोक्ता जिन्हें बिलों में छूट मिलती है, उन्हें बिजली कंपनी के हेल्प डेस्क पर पहुंचकर मोबाइल नंबर, आधार नंबर एवं जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति जमा करानी होगी। बिजली का बिल भी साथ लाना अनिवार्य होगा।

सिवनी के करीब 51750 किसानों के खाते में सब्सिडी भेजी गई है, इसलिए उनके मोबाइल पर वक्त पर मैसेज पहुंचाने के लिए कंपनी स्तर पर टेस्टिग पहले ही कर ली है। किसानों के खाते में सब्सिडी भेजने की योजना अक्टूबर से प्रारंभ हो गई है। किसानों के खाते में पैसा भी आ गया है। सिवनी के बाद छिंदवाड़ा जिले में इस योजना को लागू किया जाएगा।

व्ही किरण गोपाल, प्रबंध संचालक पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

-भरपूर जंगल और लकड़ी होने के बाद भी तख्त इंडस्ट्री नहीं, प्रदेश में दूसरे राज्यों से 25 प्रतिशत महंगा पड़ रहा फर्नीचर

लकड़ी उत्पादन में एमपी का पहला स्थान, लेकिन उद्योग एक भी नहीं

-गैस चूल्हे व कुकर बनाने वाली एक भी फैक्ट्री भी नहीं

भोपाल। विशेष संवाददाता

देश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र और लकड़ी उत्पादन क्षमता मध्यप्रदेश की है। फिर भी यहां लकड़ी के टुकड़ों से बनने वाला तख्ता बनाने की एक भी आईएसआई मार्का इंडस्ट्री नहीं हैं। प्लाईवुड निर्माण क्षेत्र में देश में हमारी हिस्सेदारी एक प्रतिशत ही है। इसके यहां 8 ही बीआईएस लाइसेंसधारी उद्योग हैं। यही कारण है कि मप्र में इंटर स्टेट टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन और कमीशन के कारण फर्नीचर का बेसिक रॉ मटेरियल दूसरे राज्यों से 25 प्रतिशत तक महंगा है। इतना ही नहीं, गैस चूल्हा और प्रेशर कुकर बनाने की एक भी आईएसआई मार्का फैक्ट्री यहां नहीं हैं।

इलेक्ट्रिक स्विच, प्लग, सॉकेट और किचन के विद्युत उपकरण निर्माण का भी उत्पादन यहां नहीं होता। मप्र सीमेंट हब है, लेकिन पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का उत्पादन भी यहां नहीं होता। भारतीय मानक ब्यूरो ने ऐसे 17 उत्पादों की सूची तैयार की है, जिनके उत्पादन और आपूर्ति की मप्र में भरपूर संभावनाएं हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर का उत्पादन यहां नहीं होता। इस बारे में बीआईएस के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रदेश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पर एमएसएमई विभाग और फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स इंड इंडस्ट्री को एक डेटा प्रेजेंटेशन दिया है। इसके मुताबिक भारतीय उद्योग 1129 प्रकार के आईएसआई मार्का उत्पाद बनाते हैं, इनमें से 265 उत्पाद ही मप्र में बनते हैं।

मप्र में एक भी लाइसेंस नहीं

ब्लॉक बोर्ड, घरेलू प्रेशर कुकर, घरेलू जरूरतों वाले स्विच, प्लग एंड सॉकेट (आउटलेट), घरेलू गैस स्टोव, किचन में इस्तेमाल होने वाले विद्युत उपकरण पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इनमें सिर्फ 1 प्रतिशत लाइसेंस। फर्श के लिए प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक, प्लाईवुड, कार्बन स्टील, कार्बन स्टील कास्ट, बिलेट सिल्लियां, ब्लूम्स-स्लैब, मरीन प्लाईवुड, सेफ्टी टॉय, हॉट रोल्ड मध्यम-उच्च तन्यता स्टील, सिंचाई उपकरण। इनमें 2 प्रतिशत। पॉलीविनाइल क्लोराइड शीथेड केबल-कॉर्ड, समर्सिबल पंप, फ्लश दरवाजे के शटर, वेल्डेड लो कार्बन स्टील सिलेंडर। इनमें 3 प्रतिशत। पीने के पानी की आपूर्ति वाले पीवीसी पाइप, हाई स्ट्रेंथ डीफोर्म्ड स्टील बार और तार, बिजली तारों के कनेक्शन वाले पाइप, पीवीसी शीथेड केबल, पीवीसी अछूता बिजली के केबल, हैवी डड्यूटी पीवीसी रोधी विद्युत केबल।

इंदौर में बन रहा फर्नीचर क्लस्टर

पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, आरसीसी पाइप और पोल, कृषि आधारित उद्योग, सिंचाई के लिए पॉलीथिलीन पाइप, उर्वरक, सिंचाई उपकरण, एमिटिंग पाइप सिस्टम, समर्सिबल पंपसेट, कृषि उपकरण, वुवेन सेक (बोरे), खिलौने, प्लाईवुड, मरीन प्लाईवुड, पेवर ब्लॉक, घरेलू प्रेशर कुकर, केमिकल उद्योग, इंडक्शन मोटर, ऑटोमोबाइल पार्ट, ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट।

उद्योगों में देश बनाम मप्र

भारत-1,129 मप्र-265 प्रतिशत-23.5

कुल लाइसेंस

भारत 39,636 मप्र-1366 प्रतिशत-3.44

देश में टॉप 10 राज्य

राज्य	स्थान	कैटेगरी	लाइसेंस
गुजरात	01	531	4547
महाराष्ट्र	02	490	4147
हरियाणा	03	344	3355
तमिलनाडु	04	294	3349
उत्तर प्रदेश	05	443	3002
पंजाब	06	295	2932
दिल्ली	07	211	2670
राजस्थान	08	290	2170
पं. बंगाल	09	321	2119
मध्यप्रदेश	10	265	1366

प्रदेश में जल्द ही फर्नीचर क्लस्टर निर्माण करने जा रहे हैं। इस क्लस्टर में फर्नीचर से जुड़े हर उद्योग एक ही स्थान पर लाएंगे। इंदौर में इसका निर्माण शुरू हो चुका है।
- ओमप्रकाश सकलेचा, एमएसएमई मंत्री

-जिले में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने मिला राष्ट्रीय सम्मान

बालाघाट कृषि विज्ञान केंद्र को मिला पहला कृषि अलर्ट अवॉर्ड

बालाघाट। संवाददाता

कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट जिले की कृषि को उतरोत्तर प्रगति के शिखर पर ले जाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। केंद्र के इन प्रयासों से विगत वर्ष जिले दो किसानों विशाल कटरे, परसवाड़ा व जियालाल राहंगडाले, बगड़मारा के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया था। इसी कड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट को देश के प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार कृषि अलर्ट- 2021 से नवाजा गया। कृषि अलर्ट अवार्ड-2021 का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) हैदराबाद एवं एपिडा भारत के सरकार के संयुक्त तत्वाधान में देश की कृषि आदान बनाने वाली प्रमुख कम्पनियों अपोलो टायर, एफएमसी, एसीई, बायर, टैफे, कृषक हाट आदि के विशेष प्रयासों से वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। पुरस्कारों के लिए देश के सभी केवीके एवं एफपीओ से प्रविष्ठियां मंगाई गयी थीं जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट को जिले कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से अंलकृत किया गया।

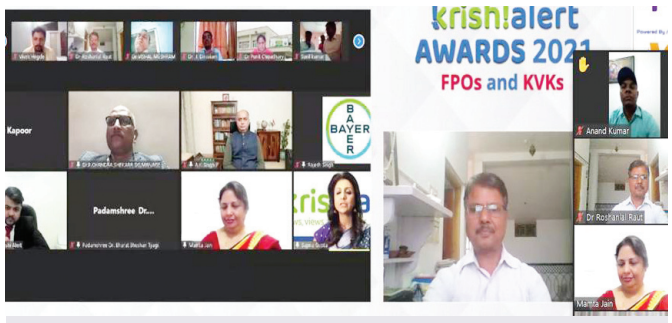

राउत ने लिया पुरस्कार

पुरस्कार प्रदान करने के लिए चयन समिति के प्रमुख डॉ. एके सिंह, उपमहानिदेशक (कृषि प्रसार) आईसीएआर नई दिल्ली एवं जूरी सदस्य डॉ. पी चन्द्रशेखर, महानिदेशक (मैनेज) हैदराबाद, डॉ. सुधांशु (एपिडा), युद्धवीर सिंह चैधरी (भारतीय किसान यूनियन), पद्मश्री भारत भूषण त्यागी द्वारा प्राप्त आवेदनों का अवलोकन कर विजेताओं का चयन किया। वर्चुअल आयोजित पुरस्कार समारोह में केद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. आरएल राऊत द्वारा पुरस्कार गृहण किया गया।

इनकी मेहनत लाई रंग

पुरस्कार स्वरूप 1100 रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। डॉ. राऊत ने बताया की पुरस्कार प्राप्त करने में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों डॉ. एसआर धुवारे, डॉ. एसके जाटव, डॉ. मुरलीधर इंगले, डॉ. रमेश अमूले, अंजना गुप्ता, धर्मेंद्र आगाशे, जितेन्द्र नगपुरे आदि द्वारा किया गया सतत प्रयास का परिणाम है।

डॉ. राउत ने माना आभार

कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉ. राऊत ने इस पुरस्कार के लिए कुलपति डॉ. प्रदीप कुमार बिसेन, जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि, जबलपुर के सतत मार्गदर्शन, डॉ. डीपी शर्मा, संचालक विस्तार सेवाएं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि, जबलपुर एवं डॉ. एसआरके सिंह, निदेशक कृषि तकनीक अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर जोन-9, जबलपुर के निर्देशन के लिए सभीका धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित किया।

अस्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए नई दरें निर्धारित

भोपाल। रबी फसलों की बुआई के साथ ही उसमें सिंचाई के लिए किसानों को अब बिजली कनेक्शन की आवश्यकता होगी। ऐसे में जो किसान सिर्फ खरीफएवं रबी फसलों की ही खेती करते हैं, वह रबी सीजन में तीन माह के लिए सिंचाई हेतु अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन लेते हैं। मध्यप्रदेश की बिजली वितरण कम्पनी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए सिंगल फेस एवं थ्री फेस के लिए नई विद्युत दरें लागू कर दी गई हैं। मध्यप्रदेश राज्य शासन के निर्णयानुसार मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए सिंगल फेस एवं थ्री फेस के लिए नई विद्युत दरें लागू कर दी गयी हैं किसान अब इन दरों पर सिंचाई के लिए अपने खेतों में कनेक्शन ले सकेंगे।

सिंगल फेस एवं थ्री फेस की नई दरें

कंपनी द्वारा जारी दरों के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्र के कृषि पंप उपभोक्ताओं को तीन माह के लिए सिंगल फेज 1 एचपी अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज, इनर्जी चार्ज सहित देय राशि 4,222 रुपए के स्थान पर अब राज्य शासन द्वारा देय सब्सिडी सहित कुल 1843 रुपए का ही भुगतान करना होगा। वहीं 2 एचपी 3480 रुपए एवं 3 एचपी के लिए मात्र 5,118 रुपए देना होगा। इसी प्रकार थ्री फेज अस्थाई 3 एचपी कृषि पंप कनेक्शन लेने वाले को तीन माह के लिए फिक्स चार्ज, इनर्जी चार्ज सहित कुल 4879 रुपए देना होगा। वहीं 5 एचपी के लिए 7,994 रुपए 7.5/8 एचपी के लिए 12,668 रुपए एवं 10 एचपी के लिए 15,784 रुपए देना होगा। कंपनी द्वारा अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन की जारी नई दरें एक नवंबर 2021 से प्रभावशील हो चुकी है।

तीन माह का अग्रिम भुगतान करना होगा जमा

कंपनी ने कहा है कि अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष 2021-22 के लिए जारी टैरिफ आदेश के अनुसार कम से कम तीन माह का अग्रिम भुगतान कंपनी में जमा कराना अनिवार्य है। विद्युत सप्लाई कोड 2013 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ऐसे उपभोक्ता जिनके पंप कनेक्शन पर उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा हुआ है, उनसे कैपेसिटर सरचार्ज का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं लिया जाएगा। कंपनी ने बताया है कि मप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफआदेश के अनुसार अस्थाई कृषि पंप की दरों का निर्धारण किया गया है। त्रैमासिक आधार पर एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर द्वारा ईंधन प्रभार की गणना की जाएगी।

दीक्षांत समारोह में मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शिरकत की, बोले

कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में सातवां दीक्षांत समारोह सम्पन्न

शिक्षा की सार्थकता तभी जब किसान हों खुशहाल

ग्वालियर। संवाददाता

कृषि विवि कृषि विकास और परिवर्तन के केंद्र बिंदु है। विवि को वैश्विक बाजार की मांग के अनुसार राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय बताना चाहिए। शिक्षा की सार्थकता तभी जब किसान खुशहाल हों। किसान की आय को दो गुना करने के प्रयास व्यवहारिक रूप से प्रदान हों। गांव में पायलट प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दें। किसान को उन्नात कृषि के लिए प्रोत्साहित करें। कृषि के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान परिवर्तनशील चुनौतियों के अनुरूप हों। किसानों को कृषि उद्यामियों के रूप में देखा जाए, जो कॉर्पोरेट उद्यामियों के साथ व्यापार करने में सक्षम और कुशल हों। यह बात राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कही।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। साथ ही विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक देकर भविष्य की कामना की। समारोह के अतिथि प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि विवि में फसलों की ओपीडी चलेगी। जिसमें कृषि संबंधी परेशानी का किसानों को कृषि विज्ञानी हल देंगे। इसके साथ ही हर दिन एक कृषि वैज्ञानिक गांव गांव जाकर किसानों को जैविक खेती व अच्छी फसल लेने के गुरु बताएगा। उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि किसान फूड प्रोसिंसग यूनिट खुद लगाए और अपनी पैदावार का खुद मुनाफा लें। इसके लिए प्रदेश सरकार पोटाटो की टिशू कल्चर लैब तैयार करने जा रहा है।

नौकरी नहीं राष्ट्रोत्थान उद्देश्य हो

कृषि मंत्री कमल पटेल ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि हमारी पढ़ाई केवल अपने एवं अपने परिवार के विकास के लिए ही नहीं हो, बल्कि समाज एवं राष्ट्रोत्थान में उसका योगदान होना चाहिए। केवल सरकारी व निजी क्षेत्र की नौकरियां पाना ही उद्देश्य न हो। हमारा उद्देश्य यह हो कि गरीबी व बेरोजगारी मिटाकर देश को आत्मनिर्भर बनाएं। आप सब नौकरी पाने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनें। कृषि उत्पादन बढ़े और खेती लाभ का धंधा बने। खेती की लागत कैसे कम हो, इसके लिए सभी विद्यार्थी काम करें। देश में छोटे कृषकों की संख्या ज्यादा है। इन सभी के कल्याण के लिए आप सब नए-नए आविष्कार करें। साथ ही ऐसे नवाचार सामने लाएं, जिससे देश का हर किसान अच्छी खेती के साथ-साथ फूड प्रोसेसिंग अपनाकर आगे बढ़े, तभी देश खुशहाल होगा।

1007 विद्यार्थियों को मिली उपाधियां

एक मई 2019 से 30 अप्रैल 2021 के बीच पढ़ाई पूरी करने वाले 1007 विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में उपाधियां प्रदान की गईं। कृषि संकाय के 8 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए गए। साथ ही स्नातक के 600, स्नातकोत्तर के 374 एवं पीएचडी के 33 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इसके अलाव आधा दर्जन विद्यार्थियों को सिरताज बहादुर सिन्हा स्मृति नगद पुरस्कार भी दिए गए। अतिथियों ने कृषि विश्वविद्यालय की स्मारिका का भी विमोचन किया।

छात्राओं ने मारी बाजी

दीक्षांत समारोह में छात्राओं ने का दबदबा रहा। स्वर्ण पदक पाने वाले कुल 8 विद्यार्थियों में से सात छात्राओं को पदक मिले। इनमें स्नातक के 4, स्नातकोत्तर व पीएचडी के 2-2 शामिल रहे। सात छात्राओं में यशी सिंह तोमर, शिवानी यादव, रवीना सिंह, पारुल उपाध्याय, निशा मिश्रा, रीमा व कविता भादू शामिल हैं। इनके अलावा हरणे अमोल रमेश को स्वर्ण पदक मिला।

भंडारण के लिए गांव तक कोल्ड चैन तैयार हो

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, वह लघु एवं सीमांत कृषकों के उत्थान में उपयोगी साबित होगा। सरकार 500 मैट्रिक टन से लेकर 8 मैट्रिक टन तक के कोल्ड स्टोर बनाने के लिए अनुदान देती है। किसान अब अपने खेत पर ही कोल्ड स्टोर बनवा सकते हैं। किसान आमदनी बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों को अपनाएं। प्रदेश में जहां वर्ष 2009-10 में उद्यानिकी का रकबा 8 लाख हैक्टेयर था जो 2021 में बढ़कर 21 लाख हैक्टेयर हो गया है। ग्वालियर व मुरैना सहित प्रदेश भर में फूड इक्युवेशन सेंटर बनाए जाएंगे। देश में सबसे अधिक फूड प्रोसेसिंग इकाइयां मध्यप्रदेश के लिए मंजूर हुई हैं।

स्वर्ण पदक जीतने पर कहा

बायोफर्टीलाइजर में रिसर्च करुंगा-

वर्ष 2016-17 में प्लांट पैथोलॉजी से पीएचडी करने वाले डॉ. हरणे अमोल रमेश का कहना है कि वह इस वक्त नागपुर केबीके में वैज्ञानिक हैं। वह जल्द ही बायोफर्टीलाइजर में रिसर्च कर किसानों को उन्नात खेती में अग्रणी बनाएंगे। जब ग्वालियर आए थे तो उन्हें व्यवहारिक समस्याएं तो रही पर पढ़ाई में कभी कोई दिक्कत नहीं आई।

उन्नात कृषि के रहस्य खोजेंगे

वर्ष 2019-20 में एमएससी डिपार्टमेंट ऑफ वैजिटेवल साइंस से पूरी करने वाली रीमा लाउत्रे का कहना था कि उनकी पढ़ाई शिक्षकों के मार्ग दर्शन से आसान हुई। उन्हें जभी परेशानी आई तो शिक्षकों ने उसका समाधान दिया। आगे कृषि के क्षेत्र में शोध कर उन्नात कृषि के रहस्य खोजेंगे।

प्लांट बायोटेक्नोलोजी से की एमएसी

स्वर्ण पदक मिलने पर निशी विश्वा का कहना था कि उन्होंने वर्ष 2018-19 में एमएससी पूरी की। उनका सब्जेक्ट प्लांट बायोटेक्नोलॉजी था। जिसमें शिक्षकों का पूरा सहयोग मिला। आज स्वर्ण पदक मिला उसमें हमारे शिक्षकों की मेहनत और मार्गदर्शन की बदौलत है।

हॉर्टी कल्चर में और शोध की जरुरत-

हॉर्टीकल्चर से वर्ष 2019 में एमएससी की पढ़ाई करने वाली रवीना सिंह का कहना था कि इस विषय पर और शोध की आवश्यकता है। जिसे आगामी दिनों में करेंगे। जिससे किसानों को नई नई तकनीक मिलेगी। मुझे जब भी परेशानी आई तो हमारे गुरु का सहयोग हमें हमेशा मिला। हम अपने देश के किसानों के लिए कुछ नया जरूर करेंगे।

मप्र के एक दर्जन कृषि विज्ञान केंद्रों का किया गया चयन

किसानों को पढ़ाया जाएगा डेयरी फार्मिंग और पशु प्रबंधन का पाठ

भोपाल। देश में एमएफ, एएच एंड डी, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए लाभदायक डेयरी फार्मिंग और पशुधन प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति आदेश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि सभी अटारी से प्राप्त जानकारी के आधार पर, इस प्रभाग द्वारा लाभदायक डेयरी फार्मिंग और पशुधन प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण नामक एक समेकित परियोजना प्रस्ताव को वित्त पोषण के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए आठ करोड़ रुपए की लागत से वित्त पोषित किया गया है। परियोजना का लक्ष्य पशुधन प्रबंधन और डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में अल्पकालिक प्रशिक्षण और ज्ञान उन्नयन के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि और पशुधन की संभावित क्षमता प्राप्त करना है।

होंगे पांच प्रशिक्षण- प्रशिक्षण मार्च, 2022 तक सफलता के पूरा किया जाना है और कोई भी अव्ययित बजट नहीं होना चाहिए। बजट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम कैश केवीके द्वारा प्रभावी ढंग से आयोजित किए जाएंगे। क्योंकि इसकी निगरानी और समीक्षा एमओएफ, एएचएंडडी द्वारा की जाएगी।

किसानों की क्षमता निर्माण नामक एक समेकित परियोजना प्रस्ताव को वर्तमान के दौरान वित्त पोषण के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। वित्तीय वर्ष इस परियोजना के लिए आठ करोड़ की लागत का वित्त पोषण किया गया है।

डॉ. वेद प्रकाश चहल, सहायक महानिदेशक, कृषि अनुसंधान भवन पूसा, नई दिल्ली

डेयरी फार्मिंग और पशुधन प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की संलग्न क्षमता निर्माण का पता लगाया जाएगा। मप्र के 12 केवीके का चयन किया गया है। जहां प्रशिक्षण के आयोजन के लिए पशु वैज्ञानिक तैनात हैं। जल्द ही राशि जारी की जाएगी।

नरेश गिरधर, प्रधान वैज्ञानिक, कृषि विस्तार विभाग (आईसीएआर) नई दिल्ली

अमेरिका की नौकरी छोड़ भक्ति बनीं गांव की शक्ति, बोलीं

सरपंच बनने के बाद जाना गांव

पिछले छह साल में छेड़छाड़, भ्रष्टाचार का एक भी केस पंचायत में नहीं आया सामने

-जब लड़कियां शादी के बारे में सोचती हैं तब मैंने लिया गांव का जिम्मा

-पंचायत में 70 प्रतिशत पक्के मकान बनवाए, हमारी पंचायत ओडीएफ

भोपाल। संवाददता

वो मेरा सरपंच चुनाव प्रचार का पहला दिन था उस दिन 12 किमी नंगे पैर चलने के बाद शाम के वक्त कच्चे मकान में मुझे एक परिवार मिला, जिसमें मां की गोद में एक छोटी बेटी और साइड में खड़े दो बच्चे दिखे। उन बच्चों के पिता ने अपनी जेब से 100 रुपए मुझ पर वार कर मुझे दे दिए। मैं उन्हें न नहीं कर पाई, क्योंकि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती थी। मन मसोसते हुए ले लिए। जब घर पहुंची। खाना खाने बैठी तो मन में बार-बार सवाल आ रहा था कि आज ये 100 रुपए जिस घर से मैं ले आई हूं, आज उन लोगों ने क्या खाना खाया होगा। ये घटना मेरी जिंदगी का टर्निंग प्वॉइंट बनी और सोचा कि अपने देश के लोगों की ही सेवा करनी है फिर मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा।

ये शब्द हैं मप्र के भोपाल की पढ़ी-लिखी सरपंच भक्ति शर्मा के। भक्ति ने एक खास चर्चा के दौरान कहा कि संयुक्त परिवार में मैं इकलौती लड़की रही, लेकिन जस्टिस के साथ पाला गया। भोपाल के नूतन कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। कॉलेज की प्रेजिडेंट भी रही, इसके बाद मैं सिविल सर्विसिस की तैयारी करने दिल्ली चली गई, लेकिन वहां सभी पेपर क्लिअर नहीं हुए। जिससे निराशा हुई। इंटरनेशनल रिलेशन्स की भी तैयारी की, लेकिन तब तक मैं सरपंच बन गई थी और अब मेरे पास समय नहीं था कि मैं इस पढ़ाई को आगे करती। 2019 में ही मैंने कानून की पढ़ाई खत्म की है। 25 साल की उम्र में मैं सरपंच बन गई।

ऐसे शुरू हुई सरपंच बनने की कहानी

सरपंच बनने की कहानी बड़े ही अलग किस्म की है। मेरे चाचा अमेरिका में रहते हैं, जो चाहते थे कि मुझे अमेरिका में ही रहना चाहिए। अमेरिका में मुझे ही पीआर सेक्टर में नौकरी भी मिल गई और यहां मेरा परिवार भोपाल में खेतीबाड़ी करता है। मेरे पिता चाहते थे कि मैं भी भारत में ही रहूं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहां क्या करूंगी, तो उन्होंने कहा कि हम सब खेतीबाड़ी करते हैं तो तुम भी वही करना। जब तुम मोटरसाइकिल चला लेती हो तो ट्रैक्टर भी चला लोगी तो मैं यहीं रुक गई। 2014 में सरपंच का चुनाव होना था, लेकिन वो 2015 में हुआ।

अमेरिका की नौकरी छोड़ बनीं सरपंच

घर में चर्चा हो रही थी कि चुनाव आ रहे हैं तो इस बार किसको खड़ा करना है। गांव के लोगों ने कहा कि इस बार कोई पढ़ा-लिखा सरपंच चाहिए। जब महिल सीट आई तो लोगों ने कहा कि भक्ति बाई चुनाव लड़ लेंगी। मप्र में महिलाओं को सम्मान से बाई कहा जाता है। मैं सीविल सर्विसिस पास नहीं कर पाई थी, लेकिन मुझमें देश की सेवा करने का जुनून था। जब गांव में गरीबी देखी तो लगा कि कुछ ऐसा करना है जहां मेरे पास पावर हो और मैं लोगों की मदद कर सकूं। मैं चुनाव जीत गई। नौकरी छोड़ दी। गांव क्या होता है, ये सरपंच बनने के बाद समझ आया।

राजनीति में जगह बनाना मुश्किल

जब प्रचार के लिए गांव में गई। हर घर की स्थिति देखी, तब लगा कि अपने गांवों को ही पहले अमेरिका बनाना होगा। इसी बीच यह भी समझ आया कि महिलाओं को राजनीति में फिट-इन करने की कोशिश की जाती है। 25 साल की उम्र में उस समय लगता था कि मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत होशियार हूं, लेकिन सिस्टम वैसे काम नहीं करता जैसे हम सोचते हैं। मैंने सीखा कि मुझे खुद के बल पर फैसले लेने होंगे, किसी की मदद नहीं लेनी है। जिस उम्र में बच्चे खूब मस्ती करते हैं, शादी के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में मेरे ऊपर 526 घर और 3 हजार लोगों की जिम्मेदारी आ गई थी।

मेरा परिवार राजनीति में नहीं

पिताजी ने कह दिया इस काम में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं खुद सब सीखूं। मेरी फैमिली ने शुरुआत के 6 महीने मेरी मदद की, सिर्फ ये समझाने के लिए कि सरपंची कैसे काम करती है। मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। सोशल वर्क ज्यादा करते हैं। मैं इकलौती थी जो राजनीति में आई। मेरे ऊपर मेरे पिता और दादा का बहुत प्रभाव रहा, लेकिन अब दोनों इस दुनिया में नहीं हैं।

चुनाव प्रचार में छिल गए थे मेरे पैर

सरपंची का चुनाव बहुत कठिन है। ये चुनाव इस बात पर लड़ा जाता है कि भक्ति बाई ने हमारे घर पानी नहीं पिया तो हम इन्हें वोट नहीं देंगे या मैं किसी के घर शादी में नहीं गई तो वे वोट नहीं देंगे। सरपंची का चुनाव राजनीतिक चुनाव नहीं होता ये वन टू वन होता है। ये चुनाव किसी पार्टी के तहत नहीं हुआ था। मध्यप्रदेश में चुनाव लोगों के बीच होता है। बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत में चार गांव आते हैं। यहां रास्ते पथरीले हैं। प्रचार करते-करते मेरे पैर छिल गए, खून निकलने लगा तो नंगे पैर चलने लगी।

आज मुझ पर करते हैं भरोसा

चुनाव प्रचार के दौरान जिस व्यक्ति ने मुझे 100 रुपए दिए थे वो मैंने आज भी संभाल कर रखे हैं। प्रचार के बाद जब घर आई तो यहां जश्न का माहौल था, लेकिन मैं उस परिवार के बारे में सोच रही थी कि उन्होंने पता नहीं आज खाना खाया होगा या नहीं। यही नहीं, बुजुर्ग महिलाएं जिनके हाथ काम करते-करते कट जाते हैं और जब वे आपके गालों को टच करती हैं तो वो टच भी प्यार लगता है। वो आपके माथे को चूमकर बुंदेलखंडी में कहती हैं कि तुम्हरी वजह से घर में आज खानो आओगो। मैंने बहुत महिलाओं के आंखों में आंसू देखे हैं। बच्चों को मुझे गले लगाते देखा है। 25 साल की लड़की पर कोई भरोसा नहीं करना चाहता था, लेकिन आज करते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हूं।

हम किसानी पर काम कर रहे

पिछले 6 सालों में अपनी पंचायत में 70 प्रतिशत पक्के मकान बनवाए। हमारी पंचायत ओडीएफ है। हमने करीबन पौने तीन करोड़ की सड़कें बनवाई हैं। हमने 11 एसएचजी में कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण दिया है। पिछले 6 साल में छेड़छाड़, भ्रष्टाचार का एक भी केस सामने नहीं आया है। हमने युवाओं को नशा न करने की सलाह दी है। हम किसानी पर काम कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में डिजिटल क्लासिस शुरू करने वाली हूं। जो एक तरह का डिजिटल स्कूल होगा। मेरे टेन्योर के दौरान कोई भी बच्चा कुपोषण से नहीं मरा। 18 लड़कियों ने लोन लेकर अपने खुद के काम शुरू किए हैं।

महिलाओं को दिखानी होगी ताकत

मैं हमेशा ऐसा मानती आई हूं कि हमारे पुरुष समाज में महिलाओं को खुद की ताकत को समझना होगा। उन्हें अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करके उसे इस्तेमाल करके उसका प्रोडक्टिव यूज करना होगा। समाज में चाहें महिला हो या पुरुष वो आप पर बातें बनाएंगे। ऐसे में आपको खुद तय करना है कि आपको उन बातों को कैसे लेना है। आप सभी को सफाई न देते घूमें। आप खुद, परिवार को और अपने ईश्वर को एक्सप्लेन करो और किसी को मत करो।

सहकारिता उपायुक्त ने किया 1.54 करोड़ रुपए का गबन

रायसेन में हड़पा किसान का मुआवजा

-एफआईआर दर्ज, अब होगी निलंबन की कार्रवाई

खंडवा/रायसेन। संवाददाता

खंडवा सहकारिता विभाग की उपायुक्त मीना डाबर पर रायसेन पुलिस ने 1.54 करोड़ रुपए गबन के मामले में आरोपी बनाकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। मीना डाबर ने रायसेन में उपायुक्त पद पर रहते हुए उस समय प्रशासक रहे नारायणसिंह हाडा एवं तत्कालीन शाखा प्रबंधक रामबाबू शर्मा सहकारिता भोपाल से साठगांठ कर किसान की जमीन को सेवा सहकारी संस्था उदयपुरा की बताकर सड़क विकास निगम से मुआवजा ले लिया। मीना डाबर समेत रामबाबू शर्मा, एनएस हाड़ा ने सांठगांठ करके स्थानीय किसान खुमानसिंह धाकड़ की जमीन सहकारी संस्था के नाम बताकर सड़क विकास निगम से 1 करोड़ 53 लाख 64 हजार 766 रुपए ले लिए और उसमें से 1.41 करोड़ रुपए निकालकर बांट लिए। वर्तमान में मीना डाबर खंडवा में सहकारिता उपायुक्त के पद पर है। डाबर रिटायर्डमेंट की कगार पर है, उनके पति खंडवा में ही शिक्षक पद से रिटायर हुए है। सहकारिता भोपाल के संयुक्त पंजीयक जगदीश कन्नौजे के मुताबिक, यदि कोर्ट में चालान पेश होता है तो मीना डाबर पर निलंबन

अब होगी वसूली

इधर, पुलिस के मुताबिक, साठगांठ कर स्थानीय किसान खुमानसिंह धाकड़ की जमीन सहकारी संस्था के नाम पर बताकर सड़क विकास निगम से एक करोड़ 53 लाख 64 हजार 766 रुपए की मुआवजा राशि प्राप्त कर ली। इसके बाद तीनों ने मिलकर उसमें से 141 करोड़ रुपए निकाल कर भ्रष्टाचार किया। जिसकी वसूली के लिए उपायुक्त सहकारिता विभाग खंडवा मीना डाबर एवं अन्य दो के खिलाफ थाना उदयपुरा जिला रायसेन में 26 अक्टूबर 2021 को केस दर्ज किया गया। इनके खिलाफ मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की कंडिका के तहत वैधानिक कार्रवाई भी होगी।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
सतनगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **सतीश उपाध्याय, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)